शहादत को सलाम

यह बहुत घृणित घटना है. जवानों की शहादत बेकार नहीं जायेगी. पूरा देश बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है.
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारतीय सेना को इतना मजबूत बनाएं कि दुश्मनों में दहशत हो

पुलवामा में हुए कायराना फिदायीन हमले में देश के 40 से अधिक जवान शहीद हो गये. इस घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया है. दुखी और आक्रोशित कर दिया है. जरूरी हो गया है कि अब सुरक्षा नीतियों की समीक्षा की जाये, सैन्य बलों को मजबूत किया जाये और आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब मिले. इसके अलावा, इस बात पर भी गौर किया जाये कि बदले की कार्रवाई व युद्धोन्माद के बीच शांति बहाली की राजनीतिक प्रक्रिया के रास्ते भी कैसे निकाले जा सकते हैं. इन्हीं बातों के मद्देनजर आज की **विशेष प्रस्तुति...**

सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कराएं

राधा कुमार
लेखिका एवं विश्लेषक

कश्मीर के पिछले पंद्रह-बीस सालों के इतिहास पर नजर डालें, तो छिटपुट आतंकी हमले होते रहे थे. लेकिन, धीरे-धीरे ऐसे हमले घटते गये थे. बड़े हमले भी हुए, लेकिन कुछ वर्षों का अंतराल बना रहा. साल 2007-08 के बाद सेना पर बड़े हमले कम होते गये, खासकर साल 2009 से लेकर 2013 तक कैजुअल्टीज कम हुईं. साल 2014 के बाद से एक बार फिर से ये आंकड़े बढ़ना शुरू हुए. सेना पर छोटे हमले बढ़े, आम नागरिकों की मौतें ज्यादा होने लगीं. इन बातों को ध्यान से देखने की जरूरत है. पुलवामा में जो हुआ है, वह भयानक है. इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री गाड़ी के साथ काफिले के बीच में पहुंच गयी और किसी को भनक नहीं लगी. खबर है कि इसे स्थानीय स्तर पर बनाया गया था. पुलवामा के इलाके फौज और पुलिस की बहुत सारी टुकड़ियां हमेशा रहती हैं और सक्रिय रहती हैं. फिर क्यों नहीं इसका पता चल सका पहले, यह सवाल है.

> सरकार से इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि सुरक्षाबलों को मजबूत वाहन दें व उन्नत श्रेणी के सुरक्षा कवच प्रदान करें.

राज्यपाल ने खुद स्वीकार किया है कि हमसे गलती हुई है. पुलिस ने एक हफ्ते पहले ही आतंकी हमले की चेतावनी दी थी. इस चेतावनी को सीआरपीएफ और राज्यपाल ने क्यों संज्ञान में नहीं लिया? इस समय सिक्योरिटी हेड खुद राज्यपाल ही हैं. फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गयी? नागरिक वाहनों को क्यों इजाजत दी गयी काफिले के गुजरने के दौरान? आंकड़े बताते हैं कि जब शांति प्रक्रिया जारी थी और बातचीत चल रही थी, सेना पर हमले भी घटते गये और लोग भी कम हताहत हुए थे. लेकिन, बातचीत खत्म कर दी गयी और अब फिर से वही खूनी मंजर जारी है. सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि सरकार बातचीत ही नहीं करना चाहती, जिसका परिणाम हिंसक और वीभत्स रूप में हमारे सामने है, हमारे इतने सुरक्षाबलों की जानें जा रही है, आम नागरिक मारे जा रहे हैं. इंसानी जान की इतनी सस्ती कीमत कभी नहीं होनी चाहिए. सरकार को अपनी राजनीति के लिए सेना के जवानों को तबाह नहीं करना चाहिए. देश की जनता को खड़े होकर कहना चाहिए, आपको एक भी जान के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है. देश में कोई ऐसा विपक्ष भी मौजूद नहीं है, जो शांति कायम करने के लिए प्रयास करे और बातचीत शुरू करे. बदले की बात करने से किसी का फायदा नहीं होने वाला. खैर, सरकार से इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि सुरक्षाबलों को मजबूत वाहन दें, उन्नत श्रेणी के सुरक्षा कवच प्रदान करें और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करायें.

इंटेलिजेंस की नाकामी का परिणाम यह हादसा

यह आतंकी घटना सुरक्षा एजेंसियों की चूक का परिणाम है और निसंदेह इस गतिविधि में पाकिस्तान का हाथ भी शामिल है. बहुत सोची-समझी साजिश के तहत इस शातिर ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया है. यह देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली घटना है. इंटेलिजेंस के लोगों ने कैसे उस वाहन को काफिले के बीच में आने दिया, यह बड़ा सवाल है. ऐसे कैसे कोई कार 100 किलो विस्फोटक सामग्री लेकर चली गयी और उसे कोई चेक करनेवाला भी नहीं था. गवर्नर साहब ने खुद स्वीकार किया है कि यह आतंकी घटना खुफिया एजेंसियों की नाकामी का परिणाम है. मुझे आशंका इस बात की भी है कि जिस तरह अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी जिस पर बात होती रहती है, कहीं अमेरिका ने दूसरा 9/11 तो नहीं होने दिया था. यहां हमें सावधान होने की जरूरत है. हर बार जब भी हम इन एजेंसियों या सरकार में बैठे लोगों से बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि हमने बहुत सी घटनायें होने से रोकी हैं, यह एक चूक हुई है बस. ऐसा हो सकता है कि वे सही ही हों, लेकिन उनकी इस बात से कोई प्रभावित नहीं होता है.

प्रो एसडी मुनि
सदस्य, कार्यकारी काउंसिल, आईडीएसए

> अगर सरकार को कुछ करना है, तो उसे तुरंत करना चाहिए. अगर दो दिन और निकल गये, तो उस गतिविधि का महत्व नहीं रह जायेगा.

यह आतंकी घटना देश के लिए झटका है. अगर सरकार को कुछ करना है, तो उन्हें तुरंत करना चाहिए. अगर दो दिन और निकल गये तो उस गतिविधि का महत्व नहीं रह जायेगा. कश्मीर घाटी में जैश-ए-मोहम्मद की सक्रियता का पता सबको है और सबको यह भी पता है कि पाकिस्तान उसका पूरा सहयोग कर रहा है. जैश-ए-मोहम्मद का कश्मीर में नेटवर्क बहुत तगड़ा है, सब जानते हैं. यह सब कोई नयी बात नहीं है. कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने का मतलब ही था कि सरकार यह मानकर चल रही थी कि सब ठीक कर देगी, लेकिन फिर भी यह घटना हुई. जबसे हमने यह ज्यादा कहना शुरू किया है कि पाकिस्तानियों को हम ठीक कर देंगे, कश्मीरियों को ठीक कर देंगे, तबसे ज्यादा समस्या शुरू हुई है. सुरक्षा मसले पर केवल सैन्य कार्रवाई से कुछ सुधर नहीं रहा है. हम अपनी नीतियों से केवल यह दिखा रहे हैं कि हम दोनों जगहों पर सबको बराबर कर देंगे और हम किसी की परवाह नहीं करते हैं. लेकिन, इसका कोई असर नहीं हो रहा है. चाहे फौज के जनरल कश्मीर जाकर बोलें या हमारे राजनेता, स्थिति सुधरी नहीं है और खराब ज्यादा हो गयी है. अब चुनाव नजदीक है, तो चुनाव तक कोई शांति प्रक्रिया भी देखने को नहीं मिलेगी. चारों तरफ प्रचार होगा कि हमने थप्पड़ का जवाब मुक्के से दिया है.

सेना को जरूरी सैन्य-संसाधन दिये जाएं

अजय साहनी
आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ

> क्या सरकार ने भारतीय सेना को इतना मजबूत बनाया है कि जवान पाकिस्तान में घुस कर लड़ाई लड़ सकें? नहीं! सरकार ने सेना को कमजोर बनाया है. इस देश में तमाम सरकारें झूठ के आधार पर नीतियां बनाती रही हैं. बीते तीस साल से यही हो रहा है.

जब भी इस तरह का कोई बड़ा हमला होता है, तो इसमें कहीं न कहीं चूक जरूर होती है. यह चूक अब एक इन्क्वॉयरी (जांच) का मुद्दा है. मोटे तौर पर देखें, तो जब भी सेना के जवानों का इस तरह कोई कॉन्वॉय (काफिला) होता है, तो जहां से चलना है और जहां जाना है, वहां तक चाकचौबंद सड़क व्यवस्था के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर सेना की नजर रहती है, ताकि कोई चूक न होने पाये. यह एक लंबी प्रक्रिया है. जाहिर है, इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया होगा, तभी चूक की स्थिति बनी होगी. यह सब एक बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि आम तौर पर इतनी बड़ी कॉन्वॉय को नहीं चलाया जाता.

ऐसे हादसों पर मीडिया में यह फैलने लगता है कि इसमें खुफिया सक्रियता में कमी थी, क्योंकि अगर खुफिया तंत्र मजबूत होता, तो हादसा होता ही नहीं. एक हद तक यह बात ठीक है, लेकिन इस बात से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. यह एक फिदायीन (सुसाइड बम्बिंग) हमला है, जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है. अफगानिस्तान में न जाने कितने हजार करोड़ झोंक दिये गये, अमेरिका ने बड़े-बड़े हथियारों-उपकरणों का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां फिदायीन हमले नहीं रुके. हालांकि, ऐसा नहीं है कि भारत में फिदायीन हमले के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता. मगर, इसके लिए जरूरी यह है कि सैन्य-क्षमता का विस्तार हो.

देशभर में चारों तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि अब भारत सरकार कुछ करे. मुझे समझ में यह नहीं आता कि सरकार को अभी कुछ क्यों करना चाहिए? सरकार बीते पांच साल से क्या कर रही थी? या पिछले दस या पंद्रह साल से क्या कर रही थी? सरकार यह कब समझेगी कि आंतरिक सुरक्षा में बहुत सारा धन-संसाधन लगाने की जरूरत है? दरअसल, इंटरनल एजेंसीज में, एक्सटर्नल एजेंसीज में, कोवर्ट ऑपरेशंस (गुप्त ऑपरेशनों) में पैसा लगाने की जरूरत है और यह काम सरकार को दशकों पहले से ही करना चाहिए था. बीते कई सालों से सरकार हमेशा रक्षा के क्षेत्र में कम पैसा खर्च कर रही है, इसका खामियाजा यह है कि हमारी सेना के पास सैन्य-संसाधनों की कमी है. हर साल सरकार रक्षा बजट में मात्र पांच-छह प्रतिशत बजट बढ़ाती है, जबकि आज इतना प्रतिशत तो मुद्रास्फीति है. इसका मतलब साफ है कि सैन्य-खर्चों में बढ़ोतरी करने की बजाय लगातार कटौती हो रही है. और सरकार यह कहती है कि वह बहुत तैयारी कर रही है. आखिर किस चीज की तैयारी कर रही है यह सरकार?

पिछले साल पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरमैन थे आरसी खंडूरी, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि भारतीय सेना के 68 प्रतिशत सैन्य-उपकरण इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं. खंडूरी ने रिपोर्ट में लिखा था कि भारत के पास इतना सैन्य-संसाधन नहीं है कि वह दस दिन तक कोई लड़ाई लड़ सके. इस रिपोर्ट पर ध्यान देने की बजाय सरकार ने खंडूरी को ही चेयरमैन पद से हटा दिया. क्या यही है सेना को मजबूत करने की तैयारी? सरकार इस रवैये से सेना को कैसे मजबूत करेगी, हादसों को कैसे रोक पायेगी?

कोई भी रणनीति सेना की क्षमता पर निर्धारित होती है. सेना के पास ताकत होगी, उसी आधार पर वह ठोस रणनीति बना पायेगी. महंगे रफायल खरीदकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बेईमानी से फुरसत जब किसी को मिले, तब तो वह किसी सैन्य-क्षमता या रणनीति पर काम करेगा! जब रणनीति नहीं होती है, तो सरकारों के पास नौटंकी होती है और बड़े-बड़े बयान होते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. रोज सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और देश के भीतर नेता वाहियात बयान देते फिर रहे हैं. इन बयानों से सेना का मनोबल कभी नहीं बढ़ सकता. उसके लिए चाहिए कि सेना को जरूरी सैन्य-संसाधन मुहैया कराये जायें, ताकि जवानों का कोई वार खाली न जाये.

इस सरकार ने पिछले पांच साल में ऐसा कोई तंत्र या रणनीति नहीं बनायी, जो ऐसे हादसे के बाद 24 घंटे के अंदर-अंदर जैश-ए-मुहम्मद के सरगना को धर दबोचे. जैश सरगना मसूद अजहर हो या हाफिज सईद, ये सब पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं. क्या सरकार ने भारतीय सेना को इतना मजबूत बनाया है कि जवान पाकिस्तान में घुस कर लड़ाई लड़ सकें? नहीं! सरकार ने सेना को कमजोर बनाया है. इस देश में तमाम सरकारें झूठ के आधार पर नीतियां बनाती रही हैं. बीते तीस साल से यही हो रहा है. हर हमले के बाद झूठे नेता बयानवीर बन जाते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा आगे कभी नहीं होगा. हमले पर हमले होते जा रहे हैं, लेकिन ये सरकारें सेना के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं. इस तरह से राष्ट्रनिर्माण संभव नहीं है और न ही इस तरह देश सशक्त बन पायेगा.

(बातचीत : वसीम अकरम)

इस मॉड्यूल का पर्दाफाश जरूरी

सुशांत सरीन
रक्षा विशेषज्ञ

> नब्बे के दशक में जब फौज और पैरामिलिट्री जवानों के काफिले चलते थे, तो उनके बीच में आने की किसी को इजाजत नहीं मिलती थी और सबको सख्ती से रोक लिया जाता था. इस सख्ती को दोबारा लागू करना पड़ेगा, अगर ऐसे हालात जारी रहे.

कुछ तो जो चूक थी, वह स्वाभाविक थी. चूंकि, एक एमपीवी हाईवे से काफिला जा रहा था, जो हद से ज्यादा बड़ा था और बहुत धीमी गति से चल रहा था. नियमानुसार, जब ऐसा काफिला जा रहा होता है, तो किसी भी अन्य वाहन को बीच में आने नहीं दिया जाता. लेकिन, लंबे समय से ऐसे खतरे का कोई अंदेशा नहीं था, और हालात सामान्य चल रहे थे. ऐसी स्थिति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि निजी वाहन धीमी गति से चल रहे काफिले से आगे निकल जाते हैं और कोई उन्हें नहीं रोकता. इस दृष्टि से देखा जाये, तो चूक तो हुई है. नब्बे के दशक में जब फौज और पैरामिलिट्री जवानों के काफिले चलते थे, तो उनके बीच में आने की किसी को इजाजत नहीं मिलती थी और सबको सख्ती से रोक लिया जाता था. इस सख्ती को दोबारा लागू करना पड़ेगा, अगर ऐसे हालात जारी रहे. नब्बे के दशक में और साल 2000 के दशक के शुरुआती सालों में फौज और सुरक्षा बल के लोग काफिलों के बीच घुसने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते थे. लेकिन, पिछले चंद सालों में ये होना शुरू हो गया है कि अगर आपने कड़ी कार्रवाई की, तो कार्रवाई करने वाले को ही लटका दिया जाता था. इसलिए, भी अब ढील देखी जाने लगी थी. और अंततः यह चूक साबित हुई. अब इन चीजों को भी बदलना पड़ेगा.

दूसरी चूक खुफिया एजेंसियों के फेल होने के रूप में हुई है. जब भी इस तरह का बड़ा हमला होता है, बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, उन्हें सक्रियता से सफल बनाने में. कहीं से बारूद आता है, कहीं पर उसको रखा जाता है, कोई वाहन की व्यवस्था करता है, फिर कोई बारूद से बम बनाता है और वाहन में प्लांट करता है. सुसाइड बॉम्बर को ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर निगरानी रखी जाती है, उसे लगातार इस कृत्य के लिए प्रेरित किया जाता है. फिर एक आदमी सारी जानकारी जुटाता है, रेकी होती है, कहीं से अंजाम पूरा करने के लिए पैसा आता है. ये तमाम बातें आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले होती हैं. ये मान लेना कि अचानक किसी के दिमाग में आ गया कि मैं फिदायीन हमलावर बन जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है. यह संभव इसलिए नहीं होता, क्योंकि बाकी चीजें इकट्ठा किये बिना इस तरह का बड़ा आतंकी हमला हो ही नहीं सकता है. चूंकि, इस तरह के हमलों में कई सारे लोग शामिल होते हैं, तो जानकारी लीक करने के और किसी को इस गतिविधि की भनक लगने का चांस बहुत बढ़ जाता है. इसीलिए, कई बार हम देखते हैं कि सुरक्षाबल किसी को हिरासत में लेते हैं और उसके ऊपर यह इल्जाम लगता है कि किसी न किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में वह शामिल था. ऐसा इसीलिए होता है, क्योंकि पहले से भनक लग जाती है. लेकिन इस मामले में, आपको कानोंकान खबर नहीं हुई. शायद, इस प्रकार की कोई जानकारी मिली थी कि कोई हमला हो सकता है. लेकिन, इसे पता नहीं लगाया जा सका कि कौन इसमें शामिल हो सकता है. कई बार आपके पास इंफॉर्मेशन आ भी रही होती है, लेकिन कहीं कुछ छूट जाता है और सबकुछ पता नहीं चल पाता, फिर किसी को आप पहले पकड़ भी नहीं पाते. हादसा जब हो जाता है, तब आप वापस जाकर देखते हैं कि क्या-क्या इंफॉर्मेशन मिली थी और आप उसके आधार पर कार्रवाई करना शुरू करते हैं. लेकिन, सैन्य संबंधी गतिविधियों में इस तरह की घटनाएं होती हैं. ये उम्मीद पाल लेना कि आपकी फौज सौ फीसदी सफल ही होगी, बेमानी है. लेकिन, कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसे हादसे न हों. इस लिहाज से चूक तो हुई है.

अब कार्रवाई शुरू होगी. फिलहाल, हमें यह भी नहीं पता कि विस्फोटक सामग्री क्या थी. क्या वह आरडीएक्स था, टीएनटी जैसा मवाद था, या फिर रोजमर्रा के घरेलू सामानों, जैसे डिटर्जेंट पाउडर आदि चीजों से बना बम था; हमें अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है. जब यह जानकारी मिल जायेगी, तब भी यह अंदाजा मिल जायेगा कि असल में चूक कहां हुई है. उम्मीद तो है कि इस तरह की गतिविधियों के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जायेगा, लेकिन समय लगेगा.

(बातचीत : देवेश)

सख्ती से दिया जाए जवाब

प्रकाश सिंह
पूर्व डीजीपी, बीएसएफ

पाकिस्तान की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और आतंकवादी संगठनों को वह खुला समर्थन अभी-भी दे रहा है. इसी का वीभत्स रूप पुलवामा में देखने को मिला है. कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर हमें अपनी नीतियों की समीक्षा करनी होगी कि आखिर कमी कहां रह गयी. कहीं तो कमजोरी रह गयी है, जिसका फायदा उन्होंने उठाया है. लोग शांति की बात करते हैं और इतने जवान मारे जा रहे हैं. अब अगर इसका सख्ती से जवाब नहीं दिया गया, तो देश में संदेश जायेगा कि यह कमजोर सरकार है. चूंकि चुनाव भी नजदीक हैं, इसलिए सरकार जरूर सख्त कदम उठायेगी. अब पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा.

पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना अब जरूरी हो गया है

डॉ ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी
रिसर्च फेलो, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए फिदायीन हमले से एक बार फिर यह बात साबित हो गयी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जो आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है. पाकिस्तान स्थिति संगठन जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया. इससे यह बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं. यह हमला भारत के खुफिया विभाग के लिए भी एक बड़ी विफलता है, क्योंकि वह इतने बड़े हमले के बारे में पहले से कुछ भी खबर नहीं दे पाया.

अब यह देखना जरूरी है कि इस बार भारत सरकार किस तरह इस हमले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश करती है. भारत के पास यही मौका है कि वह पाकिस्तान को एक जबरदस्त संदेश दे, ताकि पाकिस्तान सरकार को यह मानना पड़े कि ऐसे मानव-विरोधी संगठनों का उसे समर्थन नहीं करना चाहिए.

मेरा मानना है कि सिर्फ पाकिस्तान को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' की सूची से हटा देना ही पर्याप्त नहीं है. इस मुद्दे को सारे सबूतों के साथ, संयुक्त राष्ट्र परिषद् और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी ले जाना जरूरी है. हाफीज सईद के साथ-साथ सारे आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग करके भारत सरकार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखा सकती है. जब तक पाकिस्तान निरंतर भारत के खिलाफ ऐसे आतंकियों को समर्थन करता रहेगा, तब तक भारत के नौजवान शहीद होते रहेंगे. इसलिए हमें इसे हर हाल में रोकना ही होगा. यह तत्काल आवश्यकता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के सभी देश मिलकर पाकिस्तान को पृथक करें. पाकिस्तानी मीडिया इस हमले को एक छोटी घटना मान रहा है. वहां यह दर्शाया जा रहा है कि यह हमला भारत की ही साजिश है, जो आनेवाले चुनाव में प्रभाव डालेगा. ऐसा कहकर ही पाकिस्तान सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है.

जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सुरक्षा और भी बढ़ानी होगी, ताकि आगे ऐसे हमले न होने पायें. सुरक्षा बलों और खुफिया संगठनों के बीच बढ़िया सामंजस्य की आवश्यकता है. ऐसे संकट में एक-दूसरे पर दोषारोपण की बजाय हमें अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए और उन्हें ठीक करना चाहिए. आनेवाले दिनों में, भारत सरकार को ऐसे आतंकवादी संगठनों द्वारा हवाला फंड के हस्तांतरण की जांच करनी है. इसलिए, भारत को सारे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन और खुफिया संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा. जब तक इन आतंकी संगठनों को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी, ऐसे हमलों को रोक पाना मुश्किल होगा. हमें सतर्कता बढ़ा देनी चाहिए.